पब्लिक स्कूल

596. **श्री रामचन्द्र विकल** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पब्लिक स्कूलों को मान्यता देकर शिक्षा के क्षेत्र में वर्ग भेद को बढ़ावा दे रही है ;

(ख) क्या सरकार केन्द्रीय स्कूलों और नवोदय स्कूलों पर भारी धन लगाने के बावजूद भी पब्लिक स्कूलों को जरूरी समझती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इन पब्लिक स्कूलों को बन्द न किए जाने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा शाही) : (क) से (ग) "पब्लिक स्कूल" ऊंच फीस वसूल करने वाले और आमतौर पर अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के लिए बार-बार प्रयोग होने वाला शब्द है। एक भारतीय पब्लिक स्कूल सम्मेलन है जिसके सदस्य 57 स्कूल हैं जिनमें कुछ सैनिक स्कूल भी शामिल हैं। राज्य सरकारों/एजेंसियों अथवा माध्यमिक शिक्षा बोर्डों द्वारा इस प्रकार के स्कूलों को मान्यता प्रदान करने में कोई भेदभाव निहित नहीं है क्योंकि मान्यता के वही नियम अन्य सभी स्कूलों के लिए लागू होते हैं।

ऐसे "पब्लिक स्कूल" उस किस्म की शिक्षा प्रदान करने का काम करते हैं जिसको वे व्यक्ति चाहते हैं जो अपनी शिक्षा के ऊपर खर्च कर सकते हों। सच है कि देश में केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों की बहुत बड़ी संख्या है तथा इनकी संख्या में और आगे वृद्धि हो रही है परन्तु इन स्कूलों को विशिष्ट और विशेष प्रयोजन के लिए स्थापित किया गया है। केन्द्रीय विद्यालयों का काम मोटे तौर पर देश भर में एक समान शिक्षा माध्यम में केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चों के लिए एक समान, निरन्तर शिक्षा को सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में पर्याप्त आरक्षण सहित मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए अच्छी कोटि की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए नवोदय विद्यालयों को स्थापित किया जा रहा है। अतः केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों के वही लक्ष्य नहीं जो "पब्लिक स्कूलों" के हैं।

सरकार का पब्लिक स्कूलों की संभावना को समाप्त करने का विचार नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के स्कूलों के गठन में लोगों के संवैधानिक अधिकार निहित हैं।

दिल्ली बड़ौत सहारनपुर लाइन पर रेल गाड़ियां

597. **श्री रामचन्द्र विकल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली-बड़ौत-सहारनपुर लाइन पर यात्री गाड़ियों की संख्या बढ़ाकर वहां मेल या एक्सप्रेस गाड़ियों को चलाने का विचार रखती है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक।

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Railway Factories

598. SHRI F. M. KHAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the number of railway factories in the country together with their locations for the repair of railway coaches;

(b) whether Government have any proposal to set up more workshops in future; and

(c) if so, the details thereof and the estimated cost of these projects?